

एक नजर

मानवाधिकार से लगाया न्याय की गुहार



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। पैकोलिया थाना क्षेत्र के चांदपुर चौबे गांव की उमा देवी ने मानवाधिकार आयोग, दिल्ली को पत्र भेजकर स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि 2021 में थाना परसामपुर के थाना यश और एक सप्त ईस्वरचर ने मिलकर उनके बेटे सूरज चौबे के खिलाफ फर्जी मुकदमा चला करवाया। इस मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर एसआईटी कर रही है।

उमा देवी के मुताबिक, हरैया थानाध्यक्ष और एसआईटी प्रमारी जांच को प्रभावित करने के लिए उनके घर पर लगातार दहिश दे रहे हैं। 16 अप्रैल 2025 को भी पुलिस टीम ने उनके घर पर छापा मारा और सूरज चौबे की तलाश की। यह दहिश ऐसे समय में की गई जब उनके बेटे के खिलाफ कोई अपराधिक मुकदमा चला नहीं था।

महिला ने आरोप लगाया है कि थाना हरैया में उनके बेटे और उसके दोस्त शक्ति पांडे के खिलाफ दो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 18 मई 2025 को एसआईटी प्रमारी और हरैया थानाध्यक्ष ने शक्ति पांडे को मकसदनवा रेलवे स्टेशन (गौसा) से गिरफ्तार किया। लेकिन उन को उसका जमाना दिया गया और न ही परिजनों को कोई सूचना दी गई। इससे परिजनों को रोहित के फर्जी एनकाउंटर की आशंका है।

उमा देवी ने मानवाधिकार आयोग से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।

पत्रकार की मातृ शोक



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। पत्रकार संदेश शीवास्तव की माता जी के निधन से शोकालु सखी पत्रकारों ने प्रेस क्लब समारोह में प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपप्राध्याय के नेतृत्व में शोकसभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। संदेश शीवास्तव की माता जी मं चं महिनी श्रीवास्तव का शुक्यार को सुबह 6.00 बजे निधन हो गया था। शोकनिमा भाषाओं में दोस्तों ने 2 निमनट का मौन रख कर मृतत्मा की शांति और शोकालु परिवार को दुख की इस घड़ी में साहस प्रदान के लिये ईश्वर से प्रार्थना किया।

प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपप्राध्याय ने मृतत्मा के जीवन को समाजोपयोगी बताते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षिका के रूप में अपने कार्य से समाज का मार्गदर्शन किया। इस दौरान प्रकाश चंद्र गुप्ता, जयंत कुमार मिश्रा, राजेंद्र नाथ तिवारी, कृष्ण देव मिश्र, विपिन बिहारी तिवारी, मजहर आजाद, बृजेश कुमार शुक्ल, राघवेंद्र प्रसाद मिश्र, अनुराग कुमार श्रीवास्तव तवरेंज आलम ब्रम्हभूषण श्रीवास्तव, वशिष्ठ कुमार पांडे, देवेंद्र कांडा, चंद्र प्रकाश शर्मा, राकेश चंद्र श्रीवास्तव, सोहन सिंह, राजेंद्र, महेंद्र कुमार तिवारी, संतोष कुमार तिवारी, सुदृष्टि नारायण पिपाडी, लक्ष्मी गौतम, वशिष्ठ कुमार पांडे, सदीप सिंह, राजेश कुमार पांडे, ब्रह्मदेव पांडे, डॉ अजीत कुमार श्रीवास्तव, शिव प्रकाश गौड आदि उपस्थित रहे।

नीति आयोग की बैठक: केंद्र-राज्य टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं— मोदी

नई दिल्ली (आभा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की दसवीं गर्वर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रडमैप पर विचार-विमर्श किया गया। औपस्थित सिद्ध के बाद यह प्रधानमंत्री की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बड़ी बैठक थी।

बैठक का विषय विकसित राज्य के लिए विकसित भारत/2047 था। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आए और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुसार काम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां सभी सुविधाएं और सुविधाएँ होनी चाहिए। 1 कारों चाहिए। एक राज्य— एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में



विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने कारबल में महिलाओं की शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकें। जब लोग बदलाव महसूस करते हैं, तभी यह बदलाव मजबूत होता है और बदलाव को एक आंदोलन में बदल देता है।

उन्होंने कहा कि एक टीम के रूप में हमारे पास 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा अवसर है। हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए—2047 तक भारत को विकसित बनाना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य विकसित हो, हर नगर पालिका विकसित हो और हर गांव विकसित हो। अगर हम इन तर्ज पर काम करेंगे, तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में 10वीं गर्वर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में श्विकसित राज्य—विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए आयोजित यह बैठक राज्यों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगी। वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंडाबाबु नायडू ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए राज्य

सरकारों के तीन उप-समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनका राज्य इस राष्ट्रीय आकांक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीडीपी वृद्धि पर पहला उप-समूह निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखेगा। जनसंख्या प्रबंधन पर दूसरा उप-समूह भारत को वृद्धावस्था और कम प्रजनन क्षमता जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करतें हुए अपने जनसंख्याव्यवस्था लाम का लाम उठाते में मदद करेगा। तीसरा उप-समूह प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा। एनडीए शासित पुडुचेरी सहित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगना के मुख्यमंत्रियों एन. चंद्रबाबु नायडू, एमके स्टालिन और ए. रेवंत रेड्डी ने बैठक में शिरकत की। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया राज्य में पूर्व व्यस्तताओं में व्यस्त थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन. बालगोपाल को भेजा। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रमालासमी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।

मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलों पर विराम
काका (आभा)। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलों को फिलहाल विराम मिल गया है। योजना मामलों के सलाहकार वाहीदुद्दीन महसूद ने शनिवार को डेक्का में पत्रकारों से बातचीत में यह साफ किया कि उन यूनुस और न ही किसी की बात की है। सभी अवसर-अवसर पदों पर कायम हैं और सरकार को दिग्ग एन अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। बांग्लादेशी अखबार प्रोग्राम आलो के मुताबिक, शनिवार को डेक्का में राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद अखबार एक बंद कमरे में अंतरिम सरकार के सलाहकारों की बैठक हुई। यह बैठक पहले से तय नहीं थी।

बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर जलाये निजीकरण के दस्तावेज
को महंगी और अनियमित बिजली आपूर्ति का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने हम निजीकरण नहीं सहेंगे और बिजली विभाग हमारा है, इसे बेचना गुनाह है जैसे नारे लगाए। उन्होंने बेलावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। का अफकी लाल के साथ ही अनेक कर्मचारियों विरोध में शामिल रहे।



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। शनिवार को मुख्य अग्रोव्या कार्यालय परिसर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निजीकरण से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा का निजीकरण उपभोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। उनका मानना है कि निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देगी। इससे आम जनता

पुंछ में पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, बढ़ाया हौसला

पुंछ (आभा)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ के एक स्कूल का दौरा किया और पाकिस्तान की सीमा पर से हो रही गोलाबारी से प्रभावित छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब, आपने खतरा और थोड़ी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन चिंता न करें सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने का आका तरीका यह होना चाहिए कि आप खुद पढ़ाई करें और खुद खेलें और स्कूल में डेर सारे दोस्त बनाएं।

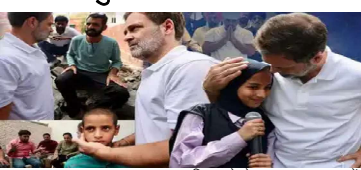
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बहुत बड़ी त्रासदी थी और इसमें कई लोगों की जान चली गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे इस

ग्राम प्रधान ने किया ढाढन तालाब में अवैध खुदाई रोकने की मांग:डीएम को सौंपा पत्र
—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। बस्ती सदर विकास खण्ड के कुसमीर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पवन कुमार यादव ने जिलाधिकारी को पत्र देकर दालाब तालाब में बिना ग्राम पंचायत के अनुमति के की जा रही खुदाई को तत्काल प्रभाव से रोकें जाने की मांग किया है। पत्र में कुसमीर ग्राम प्रधान ने कहा है कि ढाढन तालाब उनकी ग्राम पंचायत में आता है। ग्राम पंचायत के सम्पत्त परिसरपरियों का मालिक ग्राम पंचायत अख्यक्ष होता है। बिना ग्राम पंचायत के अनुमति के ढाढन तालाब में खुदाई का कार्य नियमानुसार अवैध है। ग्राम पंचायत में यदि किसी प्रकार की बिबी होती है तो शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत के ओएस.आर. के खाते में जमा होनी चाहिए। पता चला है कि किसी कम्पनी को खुदाई का आदेश दिया गया है। यह शासनादेश का खुला उल्लंघन है।

दलित मासूम बालिका की कूरता से हत्या मामले में हत्यारे गिरफ्तार न हुये तो सपा महिला मोर्चा करेगी आन्दोलन- गीता भारती

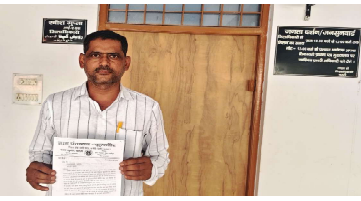
—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। शनिवार को समाजवादी पार्टी महिलासभा जिलाध्यक्ष गीता भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव में मासूम बालिका की कूरता से हत्या मामले में पीडित परिवारों से मुलाकात किया। प्रतिनिधि मण्डल ने दुखी परिवार को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में पार्टी उनके साथ खड़ी है और हत्यारों के शीघ्र गिरफ्तारी के लिये हर संभव प्रयास तेज किया जायेगा। इसी कड़ी में प्रतिनिधि मण्डल ने लालगंज थाने पर पहुंचकर बालिका हत्याकांड के बारे में जानकारी प्राप्त किया। योंके से थाने में मौजूद सीओ ने प्रतिनिधि मण्डल को बताया कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिये कड़े कदम उठाये गये हैं। इस सम्बन्ध में अभी पूरा विवरण देना संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी महिला समा जिलाध्यक्ष गीता भारती ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मासूम

बसपा को मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक में बूथ, सेक्टर को मजबूत करने पर जोर
—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। बहुजन समाज पार्टी की मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक शनिवार को बड़े हल के निकट स्थित एक मेरजहान के सम्भाग में मुख्य मण्डल प्रभारी पूर्व विधायक भगवानदास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मुख्य अतिथि एवं बस्ती, गोरखपुर, देवी पाटन मण्डल प्रभारी पूर्व विभाग परिषद सदस्य विजय प्रताप ने कहा कि बसपा पूरी ताकत से संघर्ष को मजबूत करने में जुटी है। बूथ और सेक्टर की प्रगति तैयारी और उनकी समीक्षा कर लिया जाय। विशेष अतिथि मुख्य मण्डल प्रभारी भवदेव प्रियदर्शी, सीताराम शर्मा ने कहे कि संघर्ष की मजबूती से ही सहन सुश्री मायावती के संकल्प समक्ष होंगे। इसके लिये जमीनी सारथल पर कार्यकर्ता और प्रशासकी जुट जाय और पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़े। मण्डल स्तरीय समीक्षा



मुझे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अनुरोध किया है और मैं ऐसा करूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पर से की गई गोलाबारी के पीछितों से मिलने के लिए शनिवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का दौरा किया।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोकसभा में मुलाकात की थी।



ग्राम प्रधान पवन कुमार यादव ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि ढाढन तालाब में की जा रही खुदाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाय तथा ग्रामसभा सक्षम न्यायालय में जाने को बाध्य होगी।

गीता भारती ने हत्यारे गिरफ्तार न हुये तो सपा महिला मोर्चा करेगी आन्दोलन- गीता भारती



—सपा महिलासभा प्रतिनिधि मण्डल ने दुःखी परिवार से मुलाकात कर दिया आश्वासन, पुलिस से लिया जानकारी

बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। अभी तक पुलिस दलित मासूम बेटों के हत्यारोंपरियों को नहीं पहुंच सकी है। पांच वर्ष की बच्ची संप दुई हैलापिया और हत्या की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और चिन्ताजनक है। यदि शीघ्र दोषी हत्यारे गिरफ्तार न हुये तो पार्टी संघर्ष करने को बाध्य होगी। बताया कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय

रिपेज भेज दिया जायेगा और गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देने का भी आग्रह किया जायेगा। सपा के प्रतिनिधि मण्डल में मुख्य रूप से सपा महिला समा की प्रियका पाटन, इन्दरावती शुक्ला, विजय लक्ष्मी गोमोल, प्रिया श्रीवास्तव, सुशीला गौतम, राधा देवी, उर्मिला मिश्रा, बबिता गौतम शामिल रही।



प्रसाद आजाद, अमित कुमार चौधरी, मिथीराल, राज कुमार चौधरी, जुगल किशोर चौधरी, की पी. राठौर, विनय अश्वेदकर, आशुतोष सिंह, अलीम अहमद, अनूप कुमार, भूतन कुमार, उमाशंकर, अलित आजाद, प्रदीप कुमार, दीपक, आनिल वार, अरविन्द आर्या, दिलीप बौद्ध, भारत राज, शिव कुमार गोपी चौहान, राजेंद्र, शिवम आजाद, स्थाम भवन, दीपी, सर्वनाथ, देवराज, डार रोजेश राय, राजीव कुमार के साथ ही बसपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

"युद्धो अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 25 मई 2025 रविवार

सम्पादकीय

पंचायत चुनाव की तैयारी और राजनीति

आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग 57,691 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक प्रमुख, 3,200 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। जल्द ही अधिसूचना जारी करने की संभावना है। ऐसे में निश्चित रूप से गांव की राजनीति तेजी से बदलेगी और जिस प्रकार के हालात हैं अधिकांश पदों पर काटों की टक्कर होगी। यही कारण है कि राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए करीब 1.27 लाख सीआर1 ग्रेड की मतपेटियों की खरीद के लिए ई-टेंडर भी जारी कर दिया है। पिछले चुनाव अप्रैल-मई 2021 में हुए थे, इसलिए इस बार चुनाव की अधिसूचना जनवरी या फरवरी 2026 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी दल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आशखण के बाद किस सीट पर कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। आशखण के बाद उम्मीदवारों की संभावनाओं का आकलन करना जरूरी होता है ताकि सही रणनीति बनाई जा सके। बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी होर्डिंग-पोस्टर के जरिए अपनी दांवदारी जताने लगे हैं। नेताओं और निर्वाचन आयोग की इस सक्रियता से साफ है कि पंचायत चुनाव को लेकर सियासी मशीनी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है।

पिछले पंचायत चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि पंचायत चुनावों में सत्ताधारी दल का ही हदबहा रहता है। 2021 के पंचायत चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, आम आदमी पार्टी और कई निर्दलीय उम्मीदवार नेतान में थे। कुल 3050 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी खासा दम दिखाया। भाजपा ने 768 सीटें जीतीं, सपा ने 759, बसपा ने 319, कांग्रेस 125, आरएलडी 69 और आम आदमी पार्टी 64 सीटें पर जीत हासिल की। निर्दलीयों की संख्या 944 रही। भाजपा ने निर्दलीयों को अपने साथ जोड़कर 67 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली, जबकि सपा महज पांच जिलों में ही अध्यक्ष बना सकी। यह आंकड़ा यह बताता है कि पंचायत स्तर पर भी सत्ता का प्रभाव फितना महत्वपूर्ण होता है।

पंचायत चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी संख्या की सीटें शामिल होती हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग दो तिहाई विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों से आती हैं, इसलिए पंचायत चुनाव का नतीजा सीधे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ताकत पर प्रभाव डालता है। पंचायत चुनावों में जो दल सफल होता है, उसके पास ग्रामीण वोट बैंक की मजबूत पकड़ होती है, जो आगे जाकर विधानसभा चुनावों में मददगार साबित होती है। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर हर जिले, क्षेत्र और जाति के हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं।

राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद गहन मंथन करते हैं। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय ताकत, वोट प्रतिशत, पिछली बार की तुलना में वोटों में बदोरी या कमी, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाते हैं। ये चुनाव दलों को अपनी ताकत को सही आंकने का मौका देते हैं ताकि वे कमजोर हिस्सों पर काम कर सकें। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मतों की तुलना कर दल अपने वोट बैंक में आए बदलाव का आकलन करते हैं। फिर इसके आधार पर उम्मीदवार चयन, गठबंधन और प्रचार रणनीति को दुरुस्त करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति की जमीन तैयार करते हैं। गांव की राजनीति से जुड़ी दलों की पकड़ मजबूत होकर पर विधानसभा चुनाव में भी उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। पंचायत चुनाव में मिली सफलता से नेताओं को यह भी समझने में मदद मिलती है कि किस क्षेत्र में उनकी पार्टी की पकड़ कमजोर है और वहां वे अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा, पंचायत चुनाव से दलों को जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को समझने में मदद मिलती है। साथ ही, पंचायत चुनावों में नए नेताओं को उभरने का मौका मिलता है। कई बार युवा और नए चेहरे इन चुनावों के जरिए राजनीति में आते हैं और आगे जाकर बड़े स्तर पर राजनीति में अपना मुकाम बनाते हैं। इसलिए पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर की राजनीति तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि ये प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करते हैं।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सियासी पार्टी की जंग पंचायत चुनाव से शुरू होती है और यही मुकामला विधानसभा चुनाव तक चलता रहता है। इस बार भी राजनीतिक दल पंचायत चुनावों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि वे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मंच हैं, जहां से सरकार बनने की राह दिखती है। यह चुनाव का परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मिजाज का आईना होगा।



—संजय द्विवेदी—

देश में इन दिनों राष्ट्रवाद चर्चा और बहस के केंद्र में है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम भारतीय राष्ट्रवाद पर एक नई दृष्टि से सोचें और जानें कि अखिर भारतीय भावबोध का राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र सामान्य तौर पर सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि 'भूगोल-संस्कृति-लोग' के तीन तत्वों से बनने वाली इकाई है। इन तीन तत्वों से बने राष्ट्र में अखिर सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जाहिर तौर पर वह 'लोग' ही होंगे। इसलिए लोगों की बेहतरी, मलाई, मानवता का स्पंदन ही किसी राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख तत्व होना चाहिए। जब हम लोगों की बात करते हैं तो भौगोलिक इकाईयां दृढ़ती हैं। अध्यात्म के नजरिए से पूरी दुनिया के मनुष्य एक हैं। सभी सत्त, आध्यात्मिक नेता और मनोवैज्ञानिक भी यह मानने वाले हैं कि पूरी दुनिया पर मनुष्यता एक खास भावबोध से बंधी हुयी है। यही वैश्विक अचेतन (कलेक्टिव अनकांशसस) हम-सबके एक होने का कारण है। स्वामी विवेकानंद इसी बात को कहते थे कि इस अर्थ में भारत एक जड़ भौगोलिक इकाई नहीं है। बल्कि वह एक चेतन भौगोलिक इकाई है जो सीमाओं और संरूप बलों पर ही केंद्रित नहीं है। भारतीय राष्ट्रवाद मनुष्य के विस्तार व विकास पर केंद्रित है। जिसे भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्'



कहकर संबोधित किया। यह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' राजनीतिक सत्ता का उच्चार नहीं है। उपनिषद का उच्चार है। सारी दुनिया के लोग एक परिवार, एक कुटुम्ब के हैं, इसे समझना ही दरअसल भारतीय राष्ट्रवाद को समझना है। यह राष्ट्रवाद मनुष्य की सांस्कृतिक एकता के विस्तार का प्रतीक है और हमारे सांस्कृतिक मूल्य, मानववादी सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित है। हमारी भारतीय अवधारणा में राज्य निर्मित भौगोलिक-प्रसासित इकाईयां प्रमुख स्थान नहीं रखती बल्कि हमारी चेतना, संस्कृति, भाव्य आध्यात्मीय जीवन और परंपराएं ही यहां हमें राष्ट्र बनाती हैं। हमारे सांस्कृतिक इतिहास की ओर देखें तो आर्यावर्त की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं, जबकि सच यह है कि इस पूरे भूगोल पर राज्य बहुत से थे, राजा अनेक थे—किंतु हमारा सांस्कृतिक अचेतन हमें एक राष्ट्र का अनुभव करता था। एक पेंडेंटलक सत्य यह भी यह है कि हमारा राष्ट्रवाद दरअसल राज्य संचालित नहीं था, वह समाज और बौद्धिक चेतना से संचालित था, ऋषियों द्वारा

संचालित था। वह राष्ट्रवाद इस व्यापक भूगोल की चेतना में समाया हुआ था। यहां का ज्ञान विस्तार जिस तरह चारों दिशाओं में हुआ, वह नाई हैरत में डालती है। राजा सिर्फ राज्य बनाते हैं, ऋषि अपने सांस्कृतिक अवदान से राष्ट्र बनाते हैं। आप देखें तो बुद्ध पूरी दुनिया में अपने संदेश को यूं ही नहीं फैला पाए, बल्कि उस ज्ञान में एक ऐसा नवाचार, नवचेतना था जिसे दुनिया ने स्वतः अपने बंदक ग्रहण किया। भारत कई मायनों में अध्यात्म और दुनिया की भूमि है, सच कहें तो दुनिया की समाज स्थितियों से भारत एक अलग स्थिति इसलिए पाता है, क्योंकि यह भूमि संतों के लिए, ज्ञानियों के लिए उर्वर भूमि है। दुनिया के तमाम विचारों की सांस्कृतिक चेतना जुड़ावदी है, जबकि भारत की चेतना जड़वादी है। इसलिए भारत मरता नहीं है, क्योंकि वह जड़वादी और हठवादी नहीं है। यहां का मनुष्य सांस्कृतिक एकता के लिए तो खड़ा होता है पर विचारों में जड़ता आते ही उससे अलग हो जाता है। हमारा ईश्वर

आंतरिक उन्मयन और पाप क्षय के लिए काम करता है। हमारे संत भी आध्यात्मिक उन्मयन और पापों के क्षय के लिए काम करते हैं। मनुष्य की चेतना का आत्मिक विस्तार ही इस राष्ट्रवाद लक्ष्य है। इसलिए यह सिर्फ एक खास भूगोल, एक खास विचारधारा और पूजा पंचवती में बंधे लोगों के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि समूची मानवता की मुक्ति के काम करने वाला यह विचार है। यहां मानव की मुक्ति ही उसका लक्ष्य है। यह राष्ट्रवाद सैन्यबल और व्यापार बल से चालित नहीं है, बल्कि यह चेतना के विस्तार, उसके व्यापक भावबोध और मनुष्य मात्र की मुक्ति का विचार से अनुप्राणित है। भारतीय सदन में राष्ट्रवाद को समझना वास्तव में मानवतावाद के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझना है। यह विचार कहता है—'संतों की सीकरी से क्या काम' और फिर कहता है 'कोई नृप होने हमें क्या हानि'। इस मायने में हम राज या राज्य पर निर्भर रहने वाले समाज नहीं थे। राजा या राज्य एक व्यवस्था थी, किंतु जीवन मुक्त था—मृत्यों पर आ

हित था। पूरी सांस्कृतिक परंपरा में समाज ज्यादा ताकतवर था और स्वामिना के साथ उच्च मानवतावाद और एकात्म मानवदर्शन पर आधारित जीवन जीता था। वह चीजों को खंड-खंड करके देखने का अभ्यारी नहीं था। इसलिए इस राष्ट्रवाद में जो समाज बना, वह राजा केंद्रित नहीं, संस्कृति केंद्रित समाज था। जिसे अपने होने—जीने की शर्तें पता थीं, उसे उसके कर्तव्य ज्ञात थे। उसे राज्य की सीमाएं भी पता थीं और अपनी मुक्ति के मार्ग भी पता थे। इस समाज में गुणता की स्पर्धा थी—इसलिए वह एक सुखी और संपन्न समाज था। इस समाज में भी बाजार था, किंतु समाज—बाजार के मूल्यों पर आधारित नहीं था। आनंद की सतिता पूरे समाज में बहती थी और अध्यात्मिकता के मूल्य जीवन में रसमते थे। भारतीय समाज जीवन अपनी सहिष्णुता के नाते समरसता के मूल्यों का पोषक है। इसीलिए तमाम धाराएं, विचार, धार और पंथ इस देश की हवा-मिट्टी में आए और अपना पुनर्अधिकार किया, नया रूप लिया और एकनक हो गए। भारतीयता हमारे राष्ट्रवाद का अनिवार्य तत्व है। भारतीयता का अतिवादी तत्व है। भारतीयता को स्वीकार करना और उन्हें अपने ना स्यार देना। यह राष्ट्रवाद विकसिता को साबने वाला, बहुलता को आदर देने वाला और समाज को सुख देने वाला है। इसी नाते भारत का विचार आक्रामकता का, आक्रामक का, हिंसा या अधिनायकवाद का विचार नहीं है। यह श्रेष्ठता को आदर देने वाली, विद्वानों और त्यागी जनों को पूजने वाली संस्कृति है। अपने लोकतलों को आदर देने की ही यहां राष्ट्रवाद है। इसलिए यहां भूगोल का विस्तार नहीं, मनो और दिलों को जीतने की संस्कृति यहां जहां पाती है।

यहां शांति है, सुख है, आनंद है और वैभव है। यह देकर, छोड़कर और त्यागकर मुक्त होती है। समेटना यहां ज्ञान को है, संपत्ति, जमीन और वैभव को नहीं। इसलिए फकीरी यहां आदर पाती है और सत्ताएं लांछन पाती हैं। इसलिए यहां लोकसत्ता का भी मानतावादी होना जरूरी है। यहां सत्ता विचारों से, कार्यों से और आवश्यक से लोकमानस का विचार करती है तो ही सम्मानित होती है। यही स्वामिना एक नागरिक का भी है और राष्ट्र का भी। इसलिए वह अपने अध्यात्म के पास जाता है, अपने लोक के पास जाता है और सत्ता या राज्य के चमकीले स्वप्न उसे रास नहीं आते। इसी राष्ट्र तत्व को खोजते हुए राजपुत्र सत्ता को छोड़कर बनें, जंगलों में जाते रहें, ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में, लोक के साथ स्थायक और संचाद के लिए। राम हों, कृष्ण हों, शिव हों, बुद्ध हों, महावीर हों— सब राजपुत्र हैं, संप्रभु हैं और सब राज के साथ समाज की भी साबते हैं और अपनी सार्थकता साबित करते हैं। इसलिए भारतीय जमीन का राष्ट्रवाद एक अलग कथा है, उसे वैश्वीय पैमानों से नापना जल मत होगा। आज इस वक्त जब भारतीय राष्ट्रवाद की अना—प्रनाप व्याख्या हो रही है, हमें उदरकर सोचना होगा कि क्या सच में हमने अपने राष्ट्र की थोड़ी भी समझ बची है? (लेख माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंघ विभाग के आचार्य और अध्यक्ष हैं) (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

सुरक्षा में गेम चेंजर बनी ब्रह्मोस

—एन. शशील अमित तिवारी (अ.प्र.)



महायुद्ध के दौरान वायु सेना के महाशूरी कहा करते थे कि हवाई ताकत स्वाभाविक रूप से आक्रमक होती है और इसको अपना काम करने की पूरी छूट होनी चाहिए, जीत के लिए हवाई युद्ध में श्रेष्ठता होना आवश्यक हैय बमप्रेक्ष दुश्मन की रक्षा में सेव लमा देते हैं और इसके बाद रणनीतिक बमबारी के जरिए उसकी इच्छाशक्ति को तोड़ा जा सकता है। हालिया सैन्य कार्याई में, भारतीय वायु सेना द्वारा हवा से प्रक्षेपित ब्रह्मोस का समायाजन सुबोई-30 एफकेआई लड़ाकू विमान से करने की साक्ष्यकारी फिर पुष्टि करती है कि यह सिद्धांत अभी भी उतना ही सही है, जिसकी जगह से पाकिस्तान युद्ध विमान को अग्रदूत करने को मजबूर हुआ।

1985 में भारत सरकार ने एकीकृत त गड्डूड मिसाइल विकास कार्यक्रम का पडन किया। शुरुआत में यह बैलिस्टिक मिसाइल पर केंद्रित था। लेकिन 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी वायु रक्षा प्रणालियों पर अमेरिकी युद्धतलों और हवाई जहाजों से प्रक्षेपित टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के निनाशकारी प्रभाव ने वाता को इसका दायरा बढ़ाने को प्रेरित किया। साल 1998 में ई. एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने रूसी समकक्ष के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस युद्ध उद्यम की स्थाना की गई। साल 2001 में ब्रह्मोस का पहला टेस्ट लॉच किया गया।

सकती है और फायर—ड्राफ्ट—फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। दागे जाने के बाद, यह इन्शियल नैविगेशन, उपग्रहीय मापदंडों पर निर्भर करती है भूगोलीय फ्लरेखा के इलाकों को उपयोग करके अपने लक्ष्य तक स्वायत्त रूप से पहुंचती है, और एक मीटर से भी कम की सटीकता से वार करने में समर्थ है। हवा से—सतह पर मार करने वाला इसका प्रारंभिक पर 2017 में बना और इसे 2020 में स्पेक्डान 222, टाइगर शार्क्स में शामिल किया गया था। ब्रह्मोस को इसकी परम गति, सटीकता और गतिज प्रभाव सबसे घातक वायुचरित्र के रूप में माना जाता है। ब्रह्मोस की गति से बनने वाले सीधे प्रक्षेपित प्रहार का आभास गहरे बंकरों, युद्धतलों या कमांड सेंटर तक को प्थ कर सकता है। इसकी गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से 32 गुना अधिक है।

जैसे—जैसे थल आधारित वायु रक्षा प्रणालियां अधिक सटीक एवं घातक होती जा रही, हवाई माध्यम (लड़ाकू विमान) को अपने काम को अंजाम देने में जो स्वतंत्रता पहले की हासिल थी, वह कम होती जा रही है। यूक्रेन—रूस युद्ध इसका जीवंत संकेत है। यूक्रेनी वायु सेना में अपने-अपने विमान बड़े का भारी नुकसान उठाने के बाद, दोनों भावों ने युद्धप्रस्तुत क्षेत्रों में उड़ान भरने से परहेज करते और लंबी दूरी के हवाई हथियारों पर भरोसा करना शुरू किया। यही तरीका हालिया मारत—पाक टकराव में देखने को मिला। न तो भारतीय और न ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमान एक—दूसरे देश की वायु सीमा में दाखिल हुए। पाकिस्तानी हमलों में ज्यादा निरमता दुर्घटियां निमित्त झीनों पर रही, जिनमें अधिकांश मार गिराये गये। पाकिस्तान ने 'फतह' नामक बैलिस्टिक मिसाइल का भी उपयोग किया। इन बैलिस्टिक मिसाइलों का राइबर क्रॉस—सेशन मार्ग अधिक होता है और वे एक पूर्वनिर्मात लीक, उच्च—ऊंचाई वाले परस्परलिक प्रक्षेप पथ (हाई अल्टीट्यूड पेरबालिस्टिक ट्रैजेक्टरी) का अनुसरण करती हैं। यह उनका अकालन करके, उच्च हवा में ही नष्ट करने का आसान हो जाता है। निश्चित रूप से, भारत ने तमाम हमलावर मिसाइलों को मार गिराया। इसके विपरीत, भारत ने एकदम सटीकता के साथ लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को सुबोई—30 से छोड़ा। हालांकि विस्तृत परिणाम गोपनीय ही रहेंगे, लेकिन इनकी मार का असर निश्चित है। इन मिसाइलों ने सकेत हमले के मकसद हासिल करके हुए, पायलटों के लिए न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित किया। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की अपनी क्षमता, सुपरसोनिक क्रूज प्रोफाइल के कारण, ब्रह्मोस को मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ रोक पाना लगभग असंभव है। भारतीय वैज्ञानिक पहले से ही भावों के अधिक घातक संरक्षण, ब्रह्मोस—एनजी (नैकट जेनेरेशन) विकसित करने में लगे हैं। यह छोटी और हल्की होगी और तेजसे, मित्राज और राइफल जैसे विमानों से छोड़ी जा सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह करतें वृत्त गति, दायर, मारक क्षमता या चुपके पर मार करने की विशेषता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

—डॉ. जगदीप सिंह—

भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची में इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी ईपीआईसी नंबरों की दुब्लिकेशन समस्या को हल करने के लिए नए पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लगभग दो दशक पुरानी एक तकनीकी समस्या को संबोधित करता है, जिसमें ग्लिन्स राज्यों के मतदाताओं के विभिन्न से एक ऐसे ईपीआईसी नंबर आइडेंट हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप मतदान के दौरान भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, कुछ मत अमान्य घोषित किए गए, और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे।

ईपीआईसी नंबर, जिसे आमतौर पर वोटर आईडी के रूप में जाना जाता है, भारतीय मतदाताओं की पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह प्रत्येक मतदाता को मतदाता सूची में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। इस निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। निर्वाचन आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए नए और अद्वितीय ईपीआईसी नंबरों को लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय लगभग दो दशक पुरानी एक तकनीकी समस्या को संबोधित करता है, जिसमें ग्लिन्स राज्यों के मतदाताओं के विभिन्न से एक ऐसे ईपीआईसी नंबर आइडेंट हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप मतदान के दौरान भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, कुछ मत अमान्य घोषित किए गए, और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे।

यह निर्णय निर्वाचन आयोग के डिजिटल और तकनीकी आइडेंटिकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुब्लिकेशन की समस्या को समाप्त करने के लिए डेटाबेस को अद्यतन करने और एक केंद्रीकृत त प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता थी। यह भाव्य में अन्य तकनीकी सुधारों जैसे आधार से मतदाता सूची को जोड़ने या बायोमेट्रिक सत्यापन को लागू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। साथ ही, यह निर्णय चुनावी घोषाबद्धी, जैसे लोकचैनल, को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।

ईपीआईसी नंबर दुब्लिकेशन का मुद्दा हाल के महीनों में राजनीतिक विवाद का केंद्र रहा है। गुप्तमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाकर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाये हैं। उनका आरोप था कि अनेक राज्यों के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबरों का उपयोग करके फर्जी मतदान किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान से आयोग अपनी साख में सुधार ला सकता है और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास पुनः स्थापित कर सकता है। हालांकि, कुछ दल इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने

का प्रयास करते रह सकते हैं, लेकिन अब यह मुद्दा पहले की तुलना में कम प्रभावशाली रहेगा। यह निर्णय मतदाता सूची और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इससे राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को व्यापक चुनावी सुधारों, जैसे मतदाता सूची का डिजिटलकरण, पारदर्शी मतदान प्रणाली, और ईवीएम—वीवीपेट की विश्वसनीयता पर केंद्रित के लिए प्रेरणा मिल सकती है।

हालांकि यह निर्णय साकारात्मक दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन यह निर्णय निर्वाचन आयोग के डिजिटल और तकनीकी आइडेंटिकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुब्लिकेशन की समस्या को समाप्त करने के लिए डेटाबेस को अद्यतन करने और एक केंद्रीकृत त प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता थी। यह भाव्य में अन्य तकनीकी सुधारों जैसे आधार से मतदाता सूची को जोड़ने या बायोमेट्रिक सत्यापन को लागू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। साथ ही, यह निर्णय चुनावी घोषाबद्धी, जैसे लोकचैनल, को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।



पाददर्शी बन सकेगा, जिससे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और कार्यक्षमता को बल मिलाया तथा मतदाताओं का विश्वास और बढ़ेगा। पूर्व में दुब्लिकेट ईपीआईसी नंबरों के कारण कुछ मतदाताओं को मतदान करने में कठिनाईयां का सामना करना पड़ता था, और कुछ मामलों में उनके मत अमान्य कर दिए जाते थे। अब, नए और अद्वितीय ईपीआईसी नंबरों के माध्यम से मतदाताओं को अपनी पहचान सत्यापित करने में सुविधा होगी, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक सुचारु और समझेगी बन सकेगी। यह निर्णय निर्वाचन आयोग के डिजिटल और तकनीकी आइडेंटिकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुब्लिकेशन की समस्या को समाप्त करने के लिए डेटाबेस को अद्यतन करने और एक केंद्रीकृत त प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता थी। यह भाव्य में अन्य तकनीकी सुधारों जैसे आधार से मतदाता सूची को जोड़ने या बायोमेट्रिक सत्यापन को लागू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। साथ ही, यह निर्णय चुनावी घोषाबद्धी, जैसे लोकचैनल, को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।

यह निर्णय निर्वाचन आयोग के डिजिटल और तकनीकी आइडेंटिकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुब्लिकेशन की समस्या को समाप्त करने के लिए डेटाबेस को अद्यतन करने और एक केंद्रीकृत त प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता थी। यह भाव्य में अन्य तकनीकी सुधारों जैसे आधार से मतदाता सूची को जोड़ने या बायोमेट्रिक सत्यापन को लागू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। साथ ही, यह निर्णय चुनावी घोषाबद्धी, जैसे लोकचैनल, को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।

यह निर्णय निर्वाचन आयोग के डिजिटल और तकनीकी आइडेंटिकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुब्लिकेशन की समस्या को समाप्त करने के लिए डेटाबेस को अद्यतन करने और एक केंद्रीकृत त प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता थी। यह भाव्य में अन्य तकनीकी सुधारों जैसे आधार से मतदाता सूची को जोड़ने या बायोमेट्रिक सत्यापन को लागू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। साथ ही, यह निर्णय चुनावी घोषाबद्धी, जैसे लोकचैनल, को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।

यह निर्णय निर्वाचन आयोग के डिजिटल और तकनीकी आइडेंटिकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुब्लिकेशन की समस्या को समाप्त करने के लिए डेटाबेस को अद्यतन करने और एक केंद्रीकृत त प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता थी। यह भाव्य में अन्य तकनीकी सुधारों जैसे आधार से मतदाता सूची को जोड़ने या बायोमेट्रिक सत्यापन को लागू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। साथ ही, यह निर्णय चुनावी घोषाबद्धी, जैसे लोकचैनल, को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।

नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार, नोटों को बाजारों में करते थे खपत, 100 रुपए के 32 नोट बरामद



संवाददाता-गोण्डा। पुलिस ने शनिवार को नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस अवैध कारोबार के मास्टरमिण्ड समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनके पास से ढेर सारे नकली नोट समेत रुपए छापने के अनैक उपकरण, कैमिकल, पेपर और कुछ अर्धरूप छपे हुए नोट भी बरामद हुए हैं। पुलिस के लखे चढ़े दोनों आरोपियों को हथियारों के एक्सजी न्यायालय के समक्ष शनिवार को रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया। दोनों आरोपी पूर्व में भी नकली नोट छापने के जुर्म में जेल जा चुके हैं और इनके विरुद्ध पुलिस द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।

फाइलेरिया की जांच के लिए 68 लोगों के लिए गए खून के नमूने

संवाददाता-गोण्डा। पंजरी कुपाल ब्लॉक के टिकरिया उमलून में शुक्रवार को तहल एक विशेष ग्राहट ब्लाड सर्व (एनबीएस) शिथिर आयोजित किया गया। यह शिथिर आयुधमान आरोग्य मंदिर तुलसीपुर कोठरी से जुड़े क्षेत्र में स्थानीय निवासी उत्तम के घर आयोजित हुआ। जिसमें 20 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं और पुरुषों के खून 68 रक्त नमूने लिए गए। ग्राहट ब्लाड सर्व रातु 10 से 12 बजे के बीच 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में ही किया जाता है, क्योंकि फाइलेरिया के परजीवी इसी समय रक्त में सक्रिय रहते हैं। जांच शिथिर की सफलता में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। सीफार संस्था के तकनीकी सहयोग से स्वास्थ विभाग द्वारा गड्डित सीएचओ-रोनी हिथियारक समूह (पीएससी) के सदस्य जिन्ने ग्राम प्रचार प्रतिनिधि धर्मेश मिश्रा, आशा कार्यकर्ता हसीना बानो व हसीना बेगम, एक्सजीयुटिव सुकुम पंडा, कोर्टेडार हिमन्त अली, और स्वयंसेवक फारुख व फिरोज शामिल हैं। इन लोगों ने मिलकर गांव में प्रचार-प्रसार किया। रात में जांच कराना मुश्किल, मिला पूरा सहयोग

सूचना का अधिकार कानून नागरिकों का सशक्त हथियार



संवाददाता-कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग पी एन द्विवेदी ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सशक्त बनाता है। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद करता है। उन्होंने कसया नगर के महर्षि अरविंद बिदा मोंदर में आयोजित संगोष्ठी में सूचना के अधिकार की जानकारी दी। नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी से सार्वजनिक सूचना मांग सकते हैं। अधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी। सूचना न मिलने पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी के पास पहली अपील की जा सकती है। इसके बाद भी सूचना न मिले तो आयोग में अपील की जा सकती है। सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपए शुल्क देना होगा। बीपीएल कार्ड धारकों को यह सेवा मुफ्त मिलेगी। पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने बताया कि यह कानून 2005 में बनाया गया। यह स्वतंत्र पोलिस संचालनों की जानकारी उम्मेद मायता देने वाले अधिकारी से मांगी जा सकती है। हालांकि, देश की संप्रभुता से

में आठ धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नकली नोट छापने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस ने बंधनपूर्ण अमय सिंह, एसआई उत्कर्ष पाण्डेय और विमल सिंह समेत सिपाहियों में सुनील यादव, रोशन सिंह, राम अवतार, अरविंद यादव, सुरेन्द्र कुमार, अभिषेक यादव, विनय राय महिला आरक्षी अर्चना सिंह, नीलू सिंह के नाम शामिल हैं। नकली नोट छापने के मामले में शनिवार को नवागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी चार साल पहले भी नगर कोतवाली पुलिस ने इसी आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी पर जेल से बाहर आने के कुछ दिनों के बाद दोनों ने फिर से नवागंज और अरुंधती में अपना ठिकाना बनाते हुए प्रभाई के सभी उपकरण, कैमिकल, कागज आदि जुटाकर नकली नोट छापने का काम करने लगे थे। गिरफ्तार आरोपी अर्जुन इस कारे कोतवाली का मास्टर ब्लाड बताया जाता है और नकली नोट छापने में उसे महारत हासिल है। दूसरे आरोपी इन रणियों को बाजार में खपाने का काम करता था।

मातर माता की जय के साथ निकली गई शौर्य यात्रा
संवाददाता-श्रावस्ती। कटरा बाजार में भारतीय सेना के शौर्य की सराजना करते हुए विरगा यत्रा निकली। इस दौरान ऑपरेशन सिंगरु की सफलता का जश्न मनाया गया। और जय जवान, मातर माता की जय का नारा लगाया गया। ऑपरेशन सिंगरु की सफलता और भारतीय सेना के प्लासम को समर्थन देने के लिए भारतीय सेना पाटी कार्यकर्ताओं ने विरगा यत्रा निकाली। माजपा मंडल अध्यक्ष मनोज दूबे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कटरा बाड़पास से कटरा बाजार होते हुए विरगा यत्रा निकालकर सेना के शौर्य को सलाम कर समान और आभार व्यक्त किया। मंडल अध्यक्ष मनोज दूबे ने कहा कि इतिहास में पहली बार परमाणु हथियार संपन्न देश के ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई। पहली बार सिंधु जल संधिवादी तोड़ा गया। भारतीय बापू सेना के कार्रवाई से पाकिस्तान के लगभग प्रत्येक शहर के आतंकी ठिकानों और उन क्षेत्रों पर हमला हो चुका है। महाराज प्रकाश तिवारी उर्फ बबू प्रमान ने कहा कि भारत के एयर फ़ोर्स सिरस्टन और मिसाइलों ने पाकिस्तान को खैरात मिले, अमेरिका सेना तुर्की अन्य देश के हथियारों निष्पत्ती और नष्ट कर दिया। विरगा यत्रा के दौरान मातर माता की जय, बंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद, अर्ध बंदीनारी अमर रहे के जकारों के साथ सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मोके पर अमित कुमार तिवारी, पीएल तिवारी, अधिकार दूबे, राहुलमन त्रिपाठी, पवन कुमार तिवारी, बलराज पाण्डेय सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे।

संवाददाता-महाराजगंज। गोरखपुर के विधायक में बर्ड पलू व कोआ में संक्रमण मिलने के बाद महाराजगंज में भी पशुपालन विभाग चौकाना हो गया है। जिले से कई मुर्गी फार्मों से कुल 133 मुर्गियों का सैम्पल भेजा गया, जिसके जिले रहत वाली बात है, लेकिन ने कहीं कोई संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मुर्ग के रेट में भी कोई अंतर नहीं है। पर पहले की तरह की खूब बिकी हो रही है। एहतियात के तौर पर पशुपालन विभाग लगातार जांच व साफ-सफाई करने में जुटा है। गोरखपुर के विधायक में बर्ड पलू मिलने के बाद महाराजगंज में भी अलर्ट घोषित हो गया। आनन-फ़ानन में संक्रमण की जांच व रोकथाम की कार्रवाई शुरू हो गई। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने तहसीलवार पशु चिकित्साधिकारियों की टीम गठित

कर नजर बनाए रखने व जांच करने का निर्देश दिया। फागिंग व साफ सफाई भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। महाराजगंज में करीब 25 से अधिक पोलेट्री फार्म हैं। इससे से 133 मुर्गियों का सैम्पल जांच के लिए भेजा गया। लेकिन अब तक किसी में खरटे वाली बात नहीं है। इससे जिला अब तक सफ है। हालांकि विभाग लगातार सफाई व फागिंग कर रहा है। तहसीलों में त्वरित कार्यवाही दल (आरआरटी) भी भगनगली है। प्रत्येक टीम में एक उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, अनुचर आदि शामिल हैं। अभी सफ है गोमदव व गोमृ फार्म जिलेके सी गोमदव, गुआग्रिया स्थलों, गो संक्रमण केंद्रों, कान्हा हाउस व पोलेट्री फार्म पर जरूरी दवाओं को छिड़काव कराया जा रहा है। चिकित्सकों की टीम मुर्गी फार्म व गोशालाओं का निरीक्षण कर

रहे हैं। यहां किसी पशु में पलू जैसा लक्षण नहीं आया है। ये दिखते हैं पशु पाएन विभाग से सम्पर्क करेंगे पशु चिकित्साधिकारी डॉ. हंसल प्रसाद ने बताया कि बर्ड पलू के लक्षण में खांसी, बुखार, गले में खराश, छीक, नाक बहना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पेट की समस्या है। संक्रमित जानवरों व पक्षियों के सम्पर्क में आने वाला व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो सकता है। ऐसे में ये लक्षण दिखते ही मुर्गी फार्म संचालक व गोसदन के जिम्मेदार तुरंत पशु चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करेंगे व जांच विभाग को सूचित करेंगे। मुर्ग के रेट में कोई अंतर नहीं गोरखपुर में बर्ड पलू मिलने के बाद भी महाराजगंज में बर्ड पलू को लेकर मुर्गी फार्मों पर कोई डर नहीं है। यही कारण है कि बीते दो माह से मुर्गा के रेट में कोई खास दोखा मांगते नहीं हुआ। दो माह पहले भी मुर्गा को रेट 230 से 240 रुपये प्रति किलो था और आज भी वही रेट बिक रहा है। गोरखपुर में बर्ड पलू को देखते हुए जिले में अलर्ट कर दिया गया है। हर तहसील में आरआरटी गठित कर दिया गया है। सभी पोलेट्री फार्मों व गोसदनों में दवाओं का छिड़काव शुरू करा दिया गया है। 133 सैम्पल भेजा गया, लेकिन इसमें खरटे वाली बात नहीं मिली है। डॉ. हंसल प्रसाद, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

बास से भिड़े तेंदु की मौत, इंडो-नेपाल बार्डर के पास मिला शव
संवाददाता-बहराइच। इंडो-नेपाल सीमा से 50 मीटर अंदर कर्तिया राज के कोडियाला बीट से नर तेंदु का शव शनिवार को भोर बरामद किया गया है। डीएफओ के मुताबिक बाघ व तेंदु में संघर्ष हुआ है, जिसके चलते शरान्तनी फरने की मौत हो गई। तेंदु की मौत का कारण वन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी मौत की गई है। अधिकारियों की जांच के बाद पोस्टमार्टम के बाद शव को जला दिया गया है। लुप्तप्राय वन्यजीवों की मौत से उनके सुरक्षा चुनौती बन गई है। नेपाल सीमा से लगा कर्तियाला वन्यजीव प्रभाग के कर्तिया राज का कोडियाला बीट सीमा से लगा हुआ

ऊर्जा मंत्री ने पाकिस्तान को दिया नया नाम 'पापकिस्तान'



भीख मांगने वाला देश, भारत को आंख दिखा रहा, देश विरोधी ताकतें बढ़ रही मनोबल

संवाददाता-गोण्डा। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को गोडा में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के पास अपने नागरिकों को भरपेट इंधन देने की ताकत नहीं है, वह भारत जैसे सशक्त राष्ट्र को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा- निंदोष लोगों की हत्या करने वाला देश पाक तो काई नहीं हो सकता है। ऐसे देश को तो पाकिस्तान नहीं, पापकिस्तान कहा जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की यह हिम्मत इस्लामि बूटी है क्योंकि हमारे देश में कुछ देशविरोधी ताकतें मौजूद हैं, जो उसे अग्रदक्ष समर्थन देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ताकतों को जगह जगह जवाब दिया है और भीषण में भी जाकर पड़ी तो देश जवाब देना जानता है। मंत्री ने कहा कि भारत 80 करोड़ नागरिकों को मुक्त राशन दे रहा है, जबकि पाकिस्तान में कानूनी आधारित इसका काम है। भारत हमें यह व्यक्ति को भोजन देने में सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान, जो खुद भीख मांगता है, खुद की जनता को



संवाददाता-बहराइच। पाकिस्तान के विधायक में बर्ड पलू व कोआ में संक्रमण मिलने के बाद महाराजगंज में भी पशुपालन विभाग चौकाना हो गया है। जिले से कई मुर्गी फार्मों से कुल 133 मुर्गियों का सैम्पल भेजा गया, जिसके जिले रहत वाली बात है, लेकिन ने कहीं कोई संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मुर्ग के रेट में भी कोई अंतर नहीं है। पर पहले की तरह की खूब बिकी हो रही है। एहतियात के तौर पर पशुपालन विभाग लगातार जांच व साफ-सफाई करने में जुटा है। गोरखपुर के विधायक में बर्ड पलू मिलने के बाद महाराजगंज में भी अलर्ट घोषित हो गया। आनन-फ़ानन में संक्रमण की जांच व रोकथाम की कार्रवाई शुरू हो गई। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने तहसीलवार पशु चिकित्साधिकारियों की टीम गठित

थाना समाधान दिवस पर डीएम-एसपी ने सुनी शिकायतें



मोके पर जाकर जांच करने को कहा। एक प्रमुख मामले में एक ग्रामीण ने अपने हिस्से से अधिक जमीन का बेनामा करने की शिकायत की। एसएसआई दर्ज करने और पीडित को पैसा वापस दिलाने के निर्देश दिए। तहसीलदार और लेखापाल को गांवों में जाकर अज निर्माण से जुड़े मामलों का निपटारा करने को कहा गया। यह समाधान दिवस महिने के दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद भौकते रहते हैं, भौकने दीजिए, सेना अच्छा कर रही -बृजभूषण सिंह



संवाददाता-गोण्डा। ऑपरेशन सिंगरु पर बार-बार सवाल उठ रहे हैं लेकिन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया है। गोडा में बृजभूषण सिंह ने कहा, स्वामी प्रसाद को भौकने दीजिए। इससे पहले भी बहुत मौके हैं। सेना अच्छा कर रही है। सरकार और सेना कोई भी निर्णय सोच-समझकर लेती है। इसका जवाब सही समय पर मिलेगा। स्वामी प्रसाद जैसे लोगों के बयान को कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। राहुल गांधी के विदेश नीति और राबेल पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए बृजभूषण ने कहा कि उनकी बौद्धिक क्षमता पर तरस आता है। राहुल प्रधानमंत्री को पीएम नहीं मानते। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके घर का पेट है। उन्होंने स्वामी भी पूछा- क्या राहुल गांधी को देश और सेना पर भरोसा नहीं है? बृजभूषण शरण सिंह ने गोडा में अपने निवास पर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कुशी महाकुंभ के बारे में जानकारी दी। बताया, इस प्रतियोगिता में 25 लाखों के 600 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेता परलियन विजयनाम में होने वाला अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। बृजभूषण ने कहा कि कुशी पर से संकट के बादल हट गए हैं। सभी नेमनल चैंपियनशिप समझ पर हो रही है। सरकार के पूर्ण समर्थन से कुशी की सारी गतिविधियां संच के साथ भिन्नकर चल रही हैं। गोडा के बाद बृजभूषण शरण सिंह शिवांग को एक निजी कार्यक्रम में सुलतानपुर पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह नेता प्रतिष्ठा

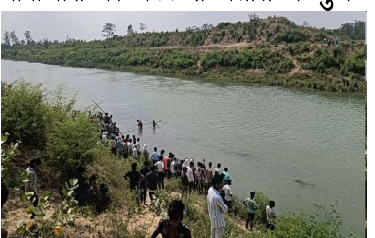
संवाददाता-श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग पी एन द्विवेदी ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सशक्त बनाता है। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद करता है। उन्होंने कसया नगर के महर्षि अरविंद बिदा मोंदर में आयोजित संगोष्ठी में सूचना के अधिकार की जानकारी दी। नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी से सार्वजनिक सूचना मांग सकते हैं। अधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी। सूचना न मिलने पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी के पास पहली अपील की जा सकती है। इसके बाद भी सूचना न मिले तो आयोग में अपील की जा सकती है। सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपए शुल्क देना होगा। बीपीएल कार्ड धारकों को यह सेवा मुफ्त मिलेगी। पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने बताया कि यह कानून 2005 में बनाया गया। यह स्वतंत्र पोलिस संचालनों की जानकारी उम्मेद मायता देने वाले अधिकारी से मांगी जा सकती है। हालांकि, देश की संप्रभुता से

संवाददाता-बहराइच। पाकी नदी के ककरा घाट पर पक्का पुल निर्माण शुरू हो गया है। श्रावस्ती विधायक राम फेरन पाण्डेय ने भूमि पुनर्वास के शनिवार को पुल की आधार शिला रखी। श्रावस्ती विधायक रामफेरन पाण्डेय के प्रयास से ककरा घाट पर पक्के पुल के निर्माण को मंजूरी मिली थी। यह पुल नरयानजोत खैरी के पास राप्ती नदी पर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की ओर से पुल का निर्माण शुरू किया गया है। 273 मीटर लंबे और 11.30 मीटर चौड़े पुल के बन जाने से दोआबा क्षेत्र के पांच वर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आम मिलेगा। पुल करने हुए विधायक रामफेरन पाण्डेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में दो बड़े नए पुल को मंजूरी दी गई है। जिसमें सिरसावा घाट पर पुल बन कर तैयार है। जबकि ककरा घाट पर पुल की आरंभ शिला रख दी गई है। इसका



संवाददाता-श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग पी एन द्विवेदी ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सशक्त बनाता है। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद करता है। उन्होंने कसया नगर के महर्षि अरविंद बिदा मोंदर में आयोजित संगोष्ठी में सूचना के अधिकार की जानकारी दी। नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी से सार्वजनिक सूचना मांग सकते हैं। अधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी। सूचना न मिलने पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी के पास पहली अपील की जा सकती है। इसके बाद भी सूचना न मिले तो आयोग में अपील की जा सकती है। सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपए शुल्क देना होगा। बीपीएल कार्ड धारकों को यह सेवा मुफ्त मिलेगी। पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने बताया कि यह कानून 2005 में बनाया गया। यह स्वतंत्र पोलिस संचालनों की जानकारी उम्मेद मायता देने वाले अधिकारी से मांगी जा सकती है। हालांकि, देश की संप्रभुता से

नहाते समय नहर में डूबे दो भाई, पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी



संवाददाता-श्रावस्ती। शनिवार की दोपहर नहाते समय दो भाई नहर में डूब गए। खबर मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। कुछ ही घंटे में लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश करने में जुटी है। मामला हरदत नगर गिरंट थाना क्षेत्र के देवरा के माजरा भाटनंदीवार गांव का है। गांव निवासी सरवर (24) पुत्र शेर अली अपने छोटे भाई बसरात (22) के साथ दोपहर को राप्ती सरयू योजक नहर में नहाने गया था। दोनों ने अपनी चप्पल, कपड़ा, साबुन, तौलिया समेत अन्य सामान नहर के किनारे रख दिया।

हुआ शिलान्यास, कई गांव को मिलेगा लाभ



संवाददाता-श्रावस्ती। राप्ती नदी के ककरा घाट पर पक्का पुल निर्माण शुरू हो गया है। श्रावस्ती विधायक राम फेरन पाण्डेय ने भूमि पुनर्वास के शनिवार को पुल की आधार शिला रखी। श्रावस्ती विधायक रामफेरन पाण्डेय के प्रयास से ककरा घाट पर पक्के पुल के निर्माण को मंजूरी मिली थी। यह पुल नरयानजोत खैरी के पास राप्ती नदी पर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की ओर से पुल का निर्माण शुरू किया गया है। 273 मीटर लंबे और 11.30 मीटर चौड़े पुल के बन जाने से दोआबा क्षेत्र के पांच वर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आम मिलेगा। पुल करने हुए विधायक रामफेरन पाण्डेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में दो बड़े नए पुल को मंजूरी दी गई है। जिसमें सिरसावा घाट पर पुल बन कर तैयार है। जबकि ककरा घाट पर पुल की आरंभ शिला रख दी गई है। इसका

उसको उठाती है। बृजभूषण ने राहुल से पूछा कि क्या आपको अपनी देश की सेना पर भरोसा नहीं है? मैं तो मानता हूँ कि आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मानने में बड़ी दिक्कत होगी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद जो है वो मेरे खानदानी का पेटेंट है। ये मेरा ही पेटेंट है। तो न मानो प्रधानमंत्री। क्या इस देश को अपना देश मानते हो? इस देश की सेना को अपनी सेना मानते तो ऐसा सवाल न करते। इसलिए मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूँ।

बैते 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंगरु के बाद अचानक सीज फायर हो गया। इस पर राहुल गांधी समेत समूचा विश्व बाइसे-किताब, संका-जोख कर रहा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच किसी भी देश ने भारत के पक्ष में खड़े न होने पर विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी खासकर विदेश मंत्री के उस बयान पर ज्यादा मुग़र थे, जिसमें विदेश मंत्री एक जयशंकर ने पाकिस्तान से जानकारी साझा करने की बात कही थी। इसी को लेकर राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं।

इसके बाद नहर में नहाने लगे। इसी समय पर फिसलने से सरवार अचानक गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए बसरात भी गहरे पानी में उतर गया। कुछ ही घंटे में दोनों भाई नहर में डूब गए। पास में मेवरी चरा रहे बरवालों ने देखा तो भागकर पहुंचे। उन्होंने गांव आकर इसकी सूचना ग्रामीणों और परिजनों को दी। खबर मिली तो परिजन और ग्रामीण भागकर पहुंचे। उधर सूचना पर नयाव तहसीलदार विजय प्रकाश गुप्ता के साथ नौके के थानाध्यक्ष सीर सिंह पुलिस स्टेशन के साथ मोके पर पहुंचे। पुलिस गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश कर रही है।

देवीपुनव व विमूनी मथर आदि तहल पहुंचने में आसानी होगी। इस भूमि पूजन में जिला पंचायत बलरामपुर प्रतिनिधि श्याम फिरोज तिवारी, उप जिलाधिकारी अमरकान्त श्रावस्ती, अतिथियों मनीष कुमार श्रावस्ती, प्रमुख प्रतिनिधि गिलोला प्रकाश चंद्र कुमार मिश्रा, कुशवाहा देवपू, वामो, बिन्नु, त्रिपाठी, चंद प्रकाश, राकेश प्रताप सिंह, सीताराम जायसवाल, स्वयंसेवक विश्वकर्मासुमित मिश्रा आदि भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

